

## शक्ति अभ्यास: दूसरे देशों के पायलटों ने उड़ाए हमारे विमान, दिखाए करतब

- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की तारीफ बोले-हमारी फोर्स दुनिया में नंबर वन

जोधपुर।

इंडियन एयर फोर्स की पहली मल्टीनेशनल एयर एंड सर्वरेज टारंग शक्ति 2024 जोधपुर के एयर एंड सर्वरेज स्टेशन पर देखें को मिली। वायुसेना की एयर एंड सर्वरेज में भारत सहित आठ देश इसमें भाग ले रहे हैं, जबकि 20 अन्य देश इसे ऑफिजल कर रहे हैं। इंडियन एयर फोर्स के इस पहले बहुराष्ट्रीय टारंग शक्ति एयरसर्वर इंजन में विदेशी वायु सेनाओं के चौंक भी खिलकर कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्प के साथ भारतीय रक्षा क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज हल्के लड़ाकू विमान, सेंसर, रक्षाएँ और एंडवर्डीनिक वायरेंटर जैसी चीजों में हम बहुत हाल तक आत्मनिर्भर हो चुके हैं और इन क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ने के लिए हम प्रयासरत हैं। टारंग शक्ति युद्धाभ्यास के दौरान गुरुवार को रक्षा मंत्री की मौजूदगी में वायुसेना ने हरतांगें करते दिखाए। भारत सहित आठ देशों की वायुसेना प्रमुखों ने एक-दूसरे के लड़ाकू विमान उड़ाए। यह नजारा देख रक्षा मंत्री ने सूख तारीफ की। उहोंने कहा कि हमारी फोर्स दुनिया में भारत काफी हाल तक आत्मनिर्भर हो गया है।



## महाकुंभ 2025: अंतरराष्ट्रीय स्तर के कुल 25 मेगा इवेंट, राष्ट्रपति मुर्मु और पीएम मोदी के कार्यक्रम

40 करोड़ के करीब श्रद्धालुओं के आने का अनुमान

प्रयागराज।

महाकुंभ 2025 को वैश्विक स्वरूप देने के लिए तैयारी तेज हुई है। संगम नगरी में दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक जनसमागम में अंतरराष्ट्रीय स्तर के कुल 25 मेगा इवेंट होने वाले हैं। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की छह इवेंट कंपनियां तय हो चुकी हैं। कंपनियों को आबद्ध करने के लिए टेंटर की वायुपत्र शुरू कर दी गई है। इन में इवेंट में राष्ट्रपति द्वारा दी गई है। इन में एयर एंडवर्डीनिक जनसमागम के एक और प्रधानमंत्री नेरेंट मंटी के एक दो योग्य राष्ट्रपति के रूप में आयोगी। राष्ट्रपति भवन और पौराणियों से तिथि के लिए योगी शासन स्तर पर वातां शुरू हो गई है। वर्ष 2019 के दिव्य व धर्म कुंभ में भी प्रधानमंत्री मोदी दो बार आए थे। तालिमीन राष्ट्रपति रामानंती को बड़ी परिवर्त के साथ आए थे। वे रात में रुक्ष भी थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के महाकुंभ के दौरान तीन से चार कार्यक्रम तय हैं। पिछले कुंभ की ही तरह इस



जारी। 06 लाख वाहनों की क्षमता वाले 92 पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे। 30 स्नान घाट बनाए जाएंगे। मंगल विमान, प्रधानमंत्री, अंतर्राष्ट्रीय विजय किरन आदि ने कहा कि महाकुंभ के दौरान 25 मेगा इवेंट के लिए तेजी से तैयारी हो गई है। इन में इवेंट के लिए एस्पर्स तारीफ की हो गई है। इन में निर्धारित की जानी है। महाकुंभ मेलाधिकारी विजय किरन आदि ने कहा कि महाकुंभ के दौरान 25 मेगा इवेंट के लिए तेजी से तैयारी हो गई है। इन में एयर एंडवर्डीनिक जनसमागम के लिए एस्परिंग विमानों की विक्रीदिग्दारी हो गई है। 1.5 लाख टायलेट्स और 26 हजार स्वच्छता कर्मचारी की तैयारी हो गई।

गहानुगम के शारीर स्नान पर्व

मकर संक्रान्ति - 15 जनवरी 2025  
मौनी अयामवर्षा - 29 जनवरी 2025  
वसंत संक्रान्ति - 03 फरवरी 2025  
महाकुंभ के प्रमुख स्नान पर्व  
पौष पूर्णिमा - 13 जनवरी 2025  
अचला सर्वमी - 04 फरवरी 2025  
माघी पूर्णिमा - 12 फरवरी 2025  
महाशिवरात्रि - 26 फरवरी 2025

महाकुंभ में आयोगी सार्वजनिक कार्यक्रम

महाकुंभ के शारीर स्नान पर्व

## **कालचक्र का बदलता स्वरूप- अमेरिका में लगातार बिगड़ती आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति**



प्रह्लाद सबनानी

अमेरिका में उच्च आय वाले क्षेत्रों में रोजगार के अवसर लगातार कम हो रहे हैं। अमेरिका में प्रति घंटा औसत मजदूरी की दर वर्ष 1973 से (मुद्रा स्फीति की दर के समायोजन के पश्चात) लगभग नहीं के बराबर बढ़ी है। अमेरिका में आय की असमानता लगातार बढ़ती जा रही है। फेडरल बजट घाटा अब अरक्षणीय (अनस्टेनेबल) स्तर पर पहुंच गया है।

संपादकीय

# शांति का रास्ता



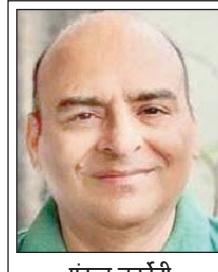
लालत गग

हिंदू विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आती जा रही है, राजनीतिक दलों में उठापटक हो रही है, दलबदल का सिलसिला जारी है, गठबंधन टूट रहे हैं जो नये जुड़ रहे हैं। प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने को आतुर भाजपा के सामने इस बार चुनौतियां कम नहीं हैं, वही कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मिली सफलता से अति-उत्साहित दिखाई दे रही है, आम आदमी पार्टी भी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करने में जुटी है। हरियाणा में तूड़ा-डाल, डाल, मैं पात-पात की कशमकश जोरों से चल रही है। विनेश और बजरंग पहलवान को शामिल करके कांग्रेस खुशियां मना रही थीं, लेकिन ह्यापह्ल से हो रहा समझौता टूटते ही कांग्रेस की खुशियां कुछ हद तक फीकी दिखाई देने लगीं। फिर भी भूपिंदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस हरियाणा में अपनी बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर रही है। भाजपा भी यहां अपनी सरकार बचाने के लिए हरसंघव प्रयास कर रही है। इस बार हरियाणा के चुनावों पर समूचे देश की नजरे लगी है। हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए विषक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की बातचीत टूटने के बाद से कांग्रेस के

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के मुद्रे पर आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट के अलटीमेटम के बावजूद अभी तक काम पर नहीं लौटे हैं, जो चिंता की बात है। इस अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ कथित दुष्कर्म और उसकी हत्या को लेकर पिछले 9 अगस्त से डॉक्टरों का आंदोलन जारी है। निसदेह यह बहुत जघण्य घटना है, जिससे हर व्यक्ति दुखी है, और उससे भी ज्यादा दुखद यह है कि अब तक पीड़िता के परिजनों को न्याय नहीं मिला है। इस मामले को लेकर पीड़िता के सहकर्मियों की हड्डताल वैधानिक और न्यायसंगत है। लोकतंत्र में राजनीतिक-सामाजिक संगठनों, व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह को अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से विरोध-प्रदर्शन और हड्डताल करने का सवैधानिक अधिकार है। लेकिन हड्डताल की वजह से सैकड़ों किलोमीटर दूर से आए मरीज और उनके तीमारदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने दावा किया है कि हड्डताल से 23 मरीजों की मौत हो गई है। जाहिर है कि इस पहलू पर मानवीय दृष्टि से विचार करते हुए डॉक्टरों को काम पर लौट आना चाहिए। वस्तुतः प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले में राज्य की पुलिस और प्रशासन ने जिस तरह से गुमराह और भ्रमित करने वाला रवैया अपनाया उससे डॉक्टरों के साथ आम लोगों में भी निराशा है। पुलिस, प्रशासन और सरकार के ऊपर से सभी का भरोसा उठ गया है। डॉक्टरों के काम पर नहीं लौटने की यह एक बड़ी वजह हो सकती है। मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आंदोलनकारी डॉक्टरों को बारी के लिए राज्य सचिवालय में आर्यन्त्रित किया था लेकिन डॉक्टरों को निमंत्रण की भाषा पर आपत्ति थी। इसलिए उन्होंने इसे ठुकरा दिया। डॉक्टरों का कहना है कि पीड़िता के परिवार को न्याय मिले और कार्यस्थल पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जब तक यह नहीं होगा हमारी हड्डताल जारी रहेगी। ये दोनों मार्गों जायज हैं और राज्य सरकार को इन्हें तुरंत मानना सुनिश्चित करना चाहिए। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं महिला है, और राज्य की मुखिया होने के नाते उनसे अपेक्षा की जाती है कि महिला प्रशिक्षु डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए वह स्वयं पहल करें।

चिंतन-मनन

# जीवन एक क्रिकेट मैच



三

**सा** वन बीत गया, भादों भी आधा निकल गया दिल्ली और उसके आसपास यमुना नदी के जल-ग्रहण क्षेत्र कहलाने वाले इलाकों में पर्याप्त पानी बरसा, लेकिन न नदी में पानी दिखा और न ही पानी से शहर की मुक्ति। जिस समय नदी में पानी लबालब होना चाहिए था, तब कम से कम दो बार दो इसमें अमोनिया की मात्रा अधिक हो गई। कई हजार करोड़ के खर्च, ढेरों वादों और योजनाओं के बाद भी लगता नहीं है न कि दिल्ली में यमुना को 2026 तक निर्मल बना देने का लक्ष्य पूरा हो पाएगा। समझना होगा कि यमुना पर लाख एसटीपी लगा कर नालों के पानी को शुद्ध कर लें लेकिन जब तक यमुना में नदी का पानी अविरल नहीं आएगा, तब तक इसके हालात तो सुधरने से रहे।

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई में यमुना में ऑक्सीजन की मात्रा शन्य पाई गई जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हआ।

करोड़ अमेरिकी डॉलर का खर्च प्रतिवर्ष किया जाता है। बेरोजगारी बीमा लाभ योजना पर भी भारी भरकम राशि अमेरिकी सरकार द्वारा प्रतिवर्ष खर्च की जाती है। अमेरिका में सेवा निवृत हो रहे कर्मचारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है जिसके कारण इस मद पर व्यय की जाने वाली राशि में भी बेतहाशा वृद्धि हो रही है, साथ ही लगातार बढ़ रहा सुरक्षा खर्च, स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय की लगातार बढ़ रही राशि के बीच वर्तमान में कर की दरों में वृद्धि नहीं करने के कारण बजटीय घाटे पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इकोनोमिक रिपोर्ट आफ द प्रेजीडेंट के अनुसार अमेरिका में वर्ष 2000 में 23,600 करोड़ अमेरिकी डॉलर का बजट आधिक्य था जो वर्ष 2001 में घटकर 12,600 करोड़ अमेरिकी डॉलर का हो गया। परन्तु, वर्ष 2002 में एक बार जो 15,800 करोड़ अमेरिकी डॉलर का बजट घाटा प्राप्त हुआ तो इसके बाद से वह बढ़ता ही गया है। वर्ष 2009 में तो बजट घाटा बढ़कर 141,300 करोड़ अमेरिकी डॉलर का हो गया, वर्ष 2010 में 129,400 करोड़ अमेरिकी डॉलर, वर्ष 2011 में 130,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर, वर्ष 2012 में 108,700 करोड़ अमेरिकी डॉलर एवं वर्ष 2020 में 313,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर, वर्ष 2021 में 277,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर एवं वर्ष 2022 में 188,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का रहा है। अमेरिका में प्रति परिवार वास्तविक औसत आय वर्ष 1973 में (वर्ष 2015 में डॉलर की कीमत पर) 50,000 अमेरिकी डॉलर थी। अमेरिका के लगभग आधे परिवारों की वास्तविक औसत आय 50,000 अमेरिकी डॉलर से

अधिक थी एवं शेष आधे परिवारों की 50,000 अमेरिका डॉलर से कम थी, जिससे आय की असमानता आज तुलना में कम दिखाई देती थी। वर्ष 1973 से वर्ष 2011 तक अमेरिका में उत्पादकता में 115 प्रतिशत की वृद्धि दर हुई है जबकि परिवारों की औसत आय (मुद्रा स्फीति वे समायोजन के बाद) केवल 11 प्रतिशत ही बढ़ी है। यह ऐसी बीच, अमेरिकी महिलाओं को भारी मात्रा में प्रदान किया गए रोजगार के अवसरों के चलते सम्भव हो पाया है। इस प्रकार, मुद्रा स्फीति के समायोजन के पश्चात, अमेरिका वर्ष 1973 के पश्चात औसत आय में वृद्धि नगण्य ही रही है। वर्ष 1973 से वर्ष 2007 के बीच अमेरिकी मध्यवर्गीय परिवारों ने उपभोग पर औसत खर्च को दुगने से भी अधिक कर दिया है। जिसके कारण इन परिवारों की बचत दर 11 प्रतिशत से घट कर 2 प्रतिशत हो गई है। बल्कि कपरिवारों को तो अपने मकानों पर ऋण लेकर एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण लेकर भी काम चलाना पड़ रहा है।

जोसेफ शूम्पर के अनुसार अमेरिका में कार ने घोड़ा गाड़ी को खत्म कर दिया एवं कम्प्यूटर ने टाइपराइटर को खत्म कर दिया। इसे हरचनात्मक विनाशह (क्रीएटिव डेस्ट्रक्शन) का नाम दिया गया, क्योंकि इससे उत्पादकता का स्तर बदल था, परंतु रोजगार के लायों अवसर समाप्त हो गए थे अमेरिका में आज 5 में से 4 रोजगार के अवसर, सेवा क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, जहां तुलनात्मक रूप से आय कम है कृषि एवं उद्योग (विनिर्माण सहित) क्षेत्रों में रोजगार वे अवसर बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हो पा रहे हैं।

# हरियाणा चुनावी मुद्दों से मिल रहे हैं सत्ता-विरोधी संकेत

जीत के सपनों को सेंध लागी है। आप ने प्रत्याशियों के दो-दो सूची जारी कर दी है, सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का एलान भी कर दिया है। फिर भी दोनों दलों में कुछ लोग हैं, जो अभी गठबंधन की उम्मीद छोड़ने के तैयार नहीं हैं, व्यापक यही गठबंधन कांग्रेस की जीत के बड़ा कारण माना जा रहा है। इस गठबंधन के टूटने से भाजपा की निराशा के बादल कुछ सीमा तक छठते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भाजपा की जीत अभी भी निश्चित नहीं मानी जा रही है। भले ही हांआपहूँ को दूर रखकर हरियाणा कांग्रेस की राज्य इकाई खुश हो रही हो, लेकिन इसका फायदा भाजपा को ही होने वाला है व्यापक हांआपहूँ प्रत्याशियों को जहां भी, जितने भी वोट मिलने वाले हैं, वे जाएंगे कांग्रेस के खाते से ही। इस त्रिकोणीय संघर्ष का फायदा भाजपा को ही मिलेगा। हरियाणा कांग्रेस एवं उसके नेता प्रारंभ से ही स्वतंत्र चुनाव लड़ने के पक्ष में रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस नेताओं के मुताबिक, दस वर्षों की सत्ता-विरोधी लहर के मद्देनजर भाजपा 2019 से कमज़ोर रिश्ति में है, जब उसे 90 सीटों की विधानसभा में 40 सीटें ही मिल पाई थीं। हाल ही में सम्पन्न लोकसभा चुनावों के नतीजे भी संकेत दें रहे हैं जहां पिछली बार की दसों सीटों की जगह उसे सिर्फ 5 सीटें मिलीं। आप को कांग्रेस के साथ गठबंधन में यहां एक लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने का मौका मिला था, लेकिन वह हार गई थी। इसी रिश्ति को देखते हुए ही प्रदेश कांग्रेस आप के साथ गठबंधन को पूरी तरह गैर जरूरी मान रहा है। लेकिन कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व राजनीति गणित को देखते हुए आप के साथ गठबंधन को लेकर निरन्तर प्रयास करता रहा। यही कारण दोनों दल गठबंधन के लिए बातचीत की मेज पर बैठे। गहुल गांधी अब लोकसभा में विषयक के नेता हैं और उनकी प्राथमिकता यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर विषयक के ईंटियर गठबंधन की एकजटता और उसकी मजबूती में किसी

तरह की कमी न दिखे ताकि केंद्र सरकार और भाजपा पर उसका दबाव बना रहे। हरियाणा में आप पार्टी कोई चमत्कार घटित करने की स्थिति में नहीं है। उसकी भूमिका सत्ता के गणित को प्रभावित करना मात्र है। कुछ सीटें उसके खाते में जा सकती हैं, जिसका रोल भविष्य की सत्ता की राजनीति में हो सकता है। अरविंद केजरीवाल के जीतीय गणित के कारण ह्याअपहू पार्टी का ग्रैस को भारी नुकसान पहुंचा सकता है तो कुछ नुकसान भाजपा का भी कर सकती है। कम वोटों के अंतर से होने वाली जीत-हार में ह्याअपहू पार्टी का असर साफ दिखने वाला है। दर से ही सही, हो सकता है कांग्रेस नेतृत्व को यह बात समझ में आ जाए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होगी। हालांकि चुनाव परिणाम आने पर ही असल माजरा समझ आएगा, लेकिन यह तय है कि भाजपा को दस साल के राज के बावजूद कमज़ोर नहीं माना जा सकता। लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटों में आई कमी के बाद विपक्ष को जो थोड़ी धार मिली है, उसका जो मनोबल बढ़ा था, उसके मद्देनजर ये चुनाव अहम माने जा रहे हैं। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव होने हैं। दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं हैं। ऐसे में हरियाणा विधानसभा चुनाव में अगर इंडिया गठबंधन साथ मिलकर मजबूती से लड़ता और अच्छी जीत दर्ज करा पाता तो उसका असर न केवल आने वाले विधानसभा चुनावों पर बल्कि पूरे विपक्ष के मनोबल पर पड़ने वाला था। इंडिया गठबंधन के कारण सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा को ही झेलना पड़ता है। इसलिये इस गठबंधन की मजबूती ही भाजपा के लिये असली चुनौती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों को याद करें तो इस पर लगभग आम राय है कि वहां कांग्रेस को प्रदेश नेतृत्व के अति आत्मविश्वास का नुकसान हुआ। असल सवाल विपक्षी वोटों के बंटवारे का है। जिस तरह से

# दिल्ली में यमुना : निर्मल होने का रास्ता चुनौतीपूर्ण

यमुना की सफाई के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को 8,500 करोड़ रुपये दिए लेकिन नीति शून्य है। असल में दिल्ली में यमुना को साफ-सुधार बनाने की जो भी नीति हैं, उनका मूल यह है कि दिल्ली में यमुना, गंगा और भूजल से 1,900 क्यूंसेक पानी प्रति दिन प्रयोग में लाया जाता है। इसका 60 फीसद यारी करीब 1,100 क्यूंसेक सीवरेज का पानी एकत्र होता है। यदि यह पानी शोधित कर यमुना में डाला जाए तो यमुना निर्मल रहेगी और दिल्ली में पेयजल की किल्लत भी दूर होगी। लेकिन हर समय नजरंदाज किया जाता है कि नदी में बाकी जल कहाँ से आएगा?

ईमानदारी की बात तो यह है कि यमुनोत्री से निकलने वाली जल-धारा, जो मैदान में आ कर गंगा की सबसे बड़ी सख्ती-सहेली कहलाती है, पहाड़ से उत्तरने के पहले ही तुप हो जाती है। दिल्ली तक जो भी जल आता है वह अधिकांशतः हरियाणा की छोटी नदियों और कारखानों के उत्सर्जन का हिस्सा होता है। बरसात के मौसम के पचहत्तर फीसद दिन बात जाने के बावजूद भी दिल्ली में एक भी बार बाढ़ नहीं आई। बाढ़ नदी में जीवन बनाए रखने में हमत्वपूर्ण भूमिका निभाती है पहाड़ों से बह कर आया पानी अपने साथ कई उपयोगी लवण लेकर आता है। वहाँ नदी के जल-मार्ग में कुड़े मलबे के कारण धारा अवरुद्ध होती है, बाढ़ उसे स्वतंत्र साफ कर देती है। इस तरह नदी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जो मछलियों और जीवों की प्रजातियों को अनुकूल परिवेश प्रदान करती है।

दिल्ली में यमुना की शुद्धि के मशीनी उपायों से कहीं ज्यादा जरूरी है कि यहाँ तसल्ली से बाढ़ आए

आखिर, दिल्ली में बाढ़ क्यों नहीं आई? कारण खोज लें तो वह भी समझ आ जाएगा कि मल-जल को साफ़ करने के उपाय क्यों असफल ही रहते हैं। यमुना की आत्मा सभी नदियों के मानिंद उसके फ्लट प्लेन अथर्व कछार में है। जब नदी यौवन पर हो तो जमीन पर जहाँ तक उसका विस्तार होता है, वह उसका कछार या फ्लट प्लेन है। अब दिल्ली में तो नदी को फैलने की जगह ही नहीं बची। हजारों निजी और सरकारी निर्माण और नदी के बीचोबीच खड़े किए गए खंभे यमुना को दिल से बहने ही नहीं देते। सुनिश्चित करने की जरूरत है कि नदी के फ्लट प्लेन का पूरी तरह से खाली रखा जाए। नदियों में आने वाली बाढ़ एक नये जीवन का निर्माण करती है, और एक तरह से जरूरी भी है। बाढ़ से नदी का जलीय जीवन भी बेहतर होता है। दिल्ली तक यमुना का अवरोध चाहने वाले दिल्ली से हरियाणा और फिर उससे ऊपर पहाड़ तक भी हैं, जिनने अवैध बाल खनन के लिए कई-कई जगह नदी के गास्ते रोके हुए हैं, या अनैतिक तरीके से इसके मार्ग को ही बदल दिया है, ऐसे लोगों की मंशा की पूर्ति के लिए पहाड़ पर ही नदी को बांधने के सरकारी प्रयास भी कम नहीं हैं। देहरादून के कालसी विकास खंड में यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचे बांध की लखवार व्यासी परियोजना 1972 में शुरू हुई। फिर इस पर काम बंद हो गया। 2014 में काम फिर शुरू हुआ और अब यमुना पहाड़ से नीचे उतरने से पहल यहाँ धेर ली जाती है। जाहिर है कि जब पहाड़ में ही यमुना का भाव नहीं है तो हथिनी कुड़े से वजीराबाद तक यह एक बरसाती नदी ही है। पहाड़ पर इतने बड़े बांध और कई सुरंगों



के जरए पानी के मार्ग को बदलने से महज जल-प्रवाह ही कम नहीं हो रहा है, बल्कि इतने निर्माण का मलबा भी बह कर नीचे आ रहा है, जो नदी को उथला बना रहा है। दिसम्बर 21 के आखिरी हफ्ते में जब व्यासी जलविद्युत परियोजना की एक टरबाइन को प्रयोग के तौर पर खोला गया तो यमुना की धारा लगभग लुप्त हो गई थी। इससे स्पष्ट हो गया था कि इस परियोजना को कारण दिल्ली तक यमुना का रास्ता अब बंद हो जाएगा।

है। जब व्यापक निर्माण के कारण पहाड़ों पर जम कर जंगल कटे जाएं तो पारिस्थितिकी हानि के कुप्रभाव से नदी भी नहीं बच सकती। महज सिंचाई और बिजली के सपने में यमुना हरियाणा में आने से पहले ही हारा जाती है। इधर, दिल्ली जिस नदी को निर्मल करने के लिए बजट बढ़ाती है, वास्तव में उस नदी का अस्तित्व है ही नहीं।











